अंक 6 माहः जनवरी 2025

विश्वत

मासिक पत्रिका

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Madhya Pradesh, Khandwa AN AISECT GROUP UNIVERSITY

विश्वविद्यालय मासिक पत्रिका

"ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिष्चला विजये
We are Energetic, Influential and are Always Committed"

मास का सूत्र

" शिक्षा केवल व्यक्तिगत प्रगति का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास का आधार भी है। एक साक्षर और शिक्षित समाज ही दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की नींव रख सकता है। "

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन

संपादकीय

सबका विकास: बजट और आम जनता

बजट किसी भी राष्ट्र की आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होता है। यह केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि सरकार की आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं और समाज के हर वर्ग के उत्थान की योजना का खाका होता है। हर वर्ष जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो आम जनता की निगाहें इस पर टिकी होती हैं—क्या महंगाई पर काबू पाया जाएगा? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होगा? क्या रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे?

बजट: आम जनता के लिए क्या मायने रखता है?
बजट सीधे तौर पर आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है। चाहे वह कर प्रणाली हो, सब्सिडी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश हो, या फिर आधारभूत संरचना का विकास—हर पहलू का प्रभाव जनता की आजीविका पर पड़ता है। इस वर्ष के बजट में जिन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

रोजगार और आजीविका - सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन पर जोर दिया है। स्टार्टअप इंडिया, मनरेगा और पीएम कौशल विकास योजना जैसी योजनाएँ युवाओं और श्रमिकों के लिए नए अवसर उपलब्ध करा सकती हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य - निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ और स्वास्थ्य योजनाएँ आम जनता के लिए राहत लेकर आती हैं। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य बीमा में बढ़ा हुआ निवेश नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार सकता है।

महंगाई और कर प्रणाली - आम नागरिकों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए बजट में करों में कुछ रियायतें दी गई हैं। साथ ही, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने के प्रयास किए गए हैं।

कृषि और ग्रामीण विकास - किसानों के लिए सब्सिडी, ऋण माफी, सिंचाई योजनाएँ, और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी घोषणाएँ कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर सकती हैं।

आधारभूत संरचना और डिजिटल इंडिया - सड़क, परिवहन, रेलवे, बिजली और इंटरनेट सेवाओं के विस्तार पर बल दिया गया है, जिससे आम जनता को अधिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

"सबका विकास" की अवधारणा और बजट की भूमिका
"सबका विकास" केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुँचाना है। यह बजट भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए गरीबों, किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और युवाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, वित्तीय समावेशन और छोटे एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं।

बजट केवल सरकार की आर्थिक योजना नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों का प्रतिबिंब भी है। यदि बजट की नीतियाँ सही दिशा में लागू की जाएँ, तो यह "सबका विकास" सुनिश्चित कर सकता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जनता बजट को केवल समाचारों तक सीमित न रखे, बल्कि इसकी नीतियों को समझे और अपने हितों के अनुसार इनका लाभ उठाए।

वृतांत

- डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, खंडवा की टीम जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता में भागीदारी दिखाई ।
- डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित हुई। कुलपति डॉ. गौरव शुक्ला ने पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक दायित्व बताया। विशेषज्ञों ने चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और नियमों पर व्याख्यान दिए।
- डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय में आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट के समन्वय से " कोप क्लब" का गठन हुआ। 25 छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता में प्रशिक्षित किया जाएगा। कुलसचिव श्री रवि चतुर्वेदी ने बताया कि यह कार्यक्रम एमओयू के तहत संचालित होगा।
- स्वामी विवेकानंद जयंती पर दो दिवसीय युवा महोत्सव आयोजित हुआ। खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को " विवेकानंद सम्मान " दिया गया। विधायक छाया मोरे ने विश्वविद्यालय चौराहे का नाम 'सी.वी. रमन चौक' रखने की घोषणा की।
- डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय के खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। पहलवान नीरज पटेल और परमजीत बारसे ने ग्रीको-रोमन कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। नेटबॉल टीम भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाएगी।
- स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस सेंटर के अंतर्गत टिमरनी गवर्नमेंट कॉलेज में आयोजित कार्यशाला में शोध और द्वि-डिग्री अवसरों पर प्रकाश डाला गया। डॉ. उमेश शर्मा ने भविष्य की सफलता के लिए कौशल विकास पर जोर दिया।
- डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि डीएसपी चयनित सुश्री रानू मोजले ने ध्वजारोहण किया। कुलसचिव श्री रवि चतुर्वेदी और कुलपति डॉ. अरुण जोशी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।
- गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय में जय हिंद अकादमी के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित हुआ। सेना व पुलिस सेवा के इच्छुक 100 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें 15 छात्र व 16 छात्राओं का प्रारंभिक चयन किया गया।
- डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय में नवगठित छात्र परिषद का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि नागार्जुन गौड़ा (आईएएस) ने छात्रों को शपथ दिलाई। डीएसपी आनंद सोनी और टीआई गायत्री सोनी ने साइबर क्राइम व यातायात पर जानकारी दी।

अंक 6, क्रमांक -2,
माहः जनवरी 2025

विश्वत

भारत बजट 2025: सबका विकास की राह पर – कृषि, मध्यम वर्ग और रोजगार सृजन के ठोस कदम

भारत सरकार ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया, जिसका मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि करना है। बजट की थीम 'सबका विकास' पर केंद्रित है, जिसमें कृषि, एमएसएमई, निवेश, और निर्यात को विकास के चार प्रमुख इंजन के रूप में पहचाना गया है।

मुख्य फोकस क्षेत्र: कृषि: 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' के तहत 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, तूर, उड़द, और मसूर जैसी दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6-वर्षीय मिशन की शुरुआत की जाएगी।

मध्यम वर्ग: आयकर स्लैब में बदलाव करते हुए, नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग की आय और खपत में वृद्धि होगी।

बजट का सारांश:

- कुल व्यय: ₹50.65 लाख करोड़
- कुल राजस्व: ₹34.96 लाख करोड़
- राजकोषीय घाटा: ₹15.69 लाख करोड़ (जीडीपी का 4.4%)
- इस बजट के माध्यम से सरकार ने आर्थिक विकास को तेज करने, मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने, और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हालांकि, दीर्घकालिक विकास के लिए कृषि, श्रम, और भूमि सुधार जैसे क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता बनी हुई है।

रोजगार सृजन: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 'ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण' कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कौशल विकास, निवेश, और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाएगा।

आर्थिक विकास और राजकोषीय नीतियां: सरकार का लक्ष्य 2025-26 में 10.1% नाममात्र जीडीपी वृद्धि हासिल करना है, जबकि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक सीमित रखना है। इसके लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने, और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।

संपादकीय मंडल

संरक्षक : प्रो. डॉ. अरुण रमेश जोशी,
कुलगुरु, सीवीआरयू खंडवा,
प्रधान संपादक : श्री रवि चतुर्वेदी, कुलसचिव, सीवीआरयू, खंडवा,
कार्यकारी संपादक : प्रो. नेहा शुक्ला, मुख्य प्रकाशन अधिकारी
साक्षी चौहान,
सदस्य : 1. डॉ. सीमा शर्मा, डायरेक्टर रिसर्च एंड इनोवेशन
2. डॉ. गणेश मलगाया, डायरेक्टर केंद्रीय प्रयोगशाला समन्वयक
3. प्रो. योगेश महाजन, तकनीकी अधिकारी, कुलगुरु सचिवालय
संकल्पना : श्री प्रमोद पटेल, ग्राफिक डिजाइनर
प्रकाशन विभाग
पवन चौरसिया, ग्राफिक डिजाइनर
संचार एवं प्रसार : श्री मनदीप सिंह पंवार, अध्ययनशाला समन्वयक
आर्यभट्ट स्कूल ऑफ डिजिटल लर्निंग
श्री हमज़ा मलिक,
वनमाली केन्द्रीय ग्रंथालय

आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार: विकास की नई दिशा

विकास अनुमान और राजकोषीय लक्ष्यों की समीक्षा

देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विकास अनुमानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर को संतुलित बनाए रखने के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पुनः परिभाषित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत सरकारी व्यय और राजस्व संग्रहण में संतुलन स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

कर प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन

वित्तीय सुधारों के तहत आयकर स्लैब में संशोधन किया गया है, जिससे मध्यम वर्गीय करदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही, माल एवं सेवा कर (GST) दरों में भी कुछ संशोधन किए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं और व्यापारियों को सुविधा मिल सके। कॉर्पोरेट कर में बदलाव से स्टार्टअप्स और कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत किया जा रहा है। फिनटेक कंपनियों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में नवाचार और डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। डिजिटल लेन-देन को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए नई नीतियां लागू की जा रही हैं, जिससे आम नागरिकों को अधिक सहूलियत मिलेगी।

मुद्रास्फीति नियंत्रण और मौद्रिक नीति के प्रभाव

देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की ओर से कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं। ब्याज दरों में संभावित परिवर्तन और मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप से महंगाई दर को स्थिर बनाए रखने की योजना बनाई जा रही है। सरकार और RBI की संयुक्त रणनीतियों से खाद्य और ईंधन की कीमतों में स्थिरता लाने की उम्मीद है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।

सरकार द्वारा किए गए आर्थिक और वित्तीय सुधारों का उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना, कर ढांचे को सरल बनाना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करना है। इन प्रयासों से देश की आर्थिक स्थिरता और विकास दर को गति मिलने की संभावना है।

शिक्षा और अनुसंधान निवेशः नवाचार और प्रगति की दिशा में बड़ा कदम

शिक्षा के लिए आवंटन में वृद्धि देश में शिक्षा क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से सरकार ने इस वर्ष शिक्षा के लिए बजट आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। उच्च शिक्षा संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह निवेश किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर छात्र तक पहुंचे और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जाए।

अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान नवाचार और वैज्ञानिक अनुसंधान को गति देने के लिए सरकार ने अनुसंधान संस्थानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इससे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में नए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जिससे स्टार्टअप्स और नवाचार को भी बल मिलेगा।

कौशल विकास कार्यक्रम देश की युवा शक्ति को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के लिए सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों के विस्तार की घोषणा की है। आईटी, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, ऑटोमोबाइल और डिजिटल क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रमाणन पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह पहल न केवल युवाओं को रोजगार योग्य बनाएगी, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी मजबूत करेगी।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है। इससे उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नई तकनीकों के विकास में तेजी आएगी। बड़े औद्योगिक घराने और स्टार्टअप्स शिक्षा और अनुसंधान परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं, जिससे देश में शोध और विकास (R&D) का एक नया युग प्रारंभ होने की उम्मीद है।

सरकार की इन पहलों से शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में व्यापक सुधार की संभावना है, जिससे देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाया जा सकेगा और भारत को वैश्विक स्तर पर नवाचार और अनुसंधान में अग्रणी बनाने की दिशा में मजबूत आधार मिलेगा।

स्थिरता और हरित विकासः बजटीय समर्थन और नवीन पहल

नई दिल्ली, 14 फरवरी 2025: हरित प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में बजटीय समर्थन की घोषणा की है। इस पहल के तहत नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन शमन, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, और पर्यावरण-केंद्रित अनुसंधान को वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा।

हरित प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ प्रथाओं के लिए बजटीय समर्थन

सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में हरित विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इस वर्ष, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और जैव-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही, उद्योगों में ऊर्जा दक्षता सुधारने के लिए टिकाऊ उत्पादन तकनीकों को अपनाने पर विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए ग्रीन बॉन्ड्स और टैक्स छूट जैसी योजनाओं की भी घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत, स्वच्छ ऊर्जा कंपनियों और नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए वित्त पोषण

जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन के तहत, अगले पांच वर्षों में सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की उत्पादन क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ऊर्जा तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी।

कई निजी निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की घोषणा की है। हाल ही में, एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने भारत में 10 बिलियन डॉलर के ग्रीन फंड की स्थापना करने की योजना बनाई है, जिससे स्थायी ऊर्जा परियोजनाओं को गति मिलेगी।

पर्यावरण विज्ञान और स्थिरता-केंद्रित शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहन

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। ग्रीन रिसर्च इनिशिएटिव के तहत, नई स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसके अलावा, स्कूली और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में पर्यावरण अध्ययन और सतत विकास को एकीकृत किया जाएगा। विद्यार्थियों को सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से हरित समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

हरित विकास और स्थिरता की दिशा में भारत सरकार के इन प्रयासों से देश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, टिकाऊ औद्योगिक विकास, और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। इन पहलों से भारत न केवल जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती का सामना कर सकेगा, बल्कि एक स्वच्छ, हरित, और टिकाऊ भविष्य की ओर भी अग्रसर होगा।

अंक 6, क्रमांक -4,
माहः जनवरी 2025

विश्वत

स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा: सुधार और भविष्य की योजनाएं

स्वास्थ्य सेवा विस्तार: स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के उपाय

देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन चुका है। सरकार द्वारा अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाने और टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उन्नत किया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवा आपूर्ति योजनाओं की घोषणा की है, जिससे गरीब और वंचित वर्गों को सीधे लाभ मिलेगा।

समाज कल्याण कार्यक्रम: वंचितों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन

सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई योजनाओं को लागू किया है। महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाएँ शुरू की गई हैं। मातृत्व लाभ योजना और किशोरी स्वास्थ्य योजना जैसी पहलों ने महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल हेल्थ क्लीनिक और आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही, समाज के वंचित वर्गों के लिए वित्तीय सहायता और बीमा योजनाओं का विस्तार किया गया है ताकि वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें।

स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए भविष्य की योजनाएं

भविष्य की योजनाओं में शिक्षा के साथ स्वास्थ्य देखभाल का एकीकरण एक महत्वपूर्ण पहलू है। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाने के लिए स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार कर रही है ताकि सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह ले सकें।सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को सुलभ बनाने की दिशा में भी काम किया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके। आगामी वर्षों में, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण को और अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए नई तकनीकों और डिजिटल समाधानों को अपनाने की योजना बनाई गई है।

स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा में सुधार की दिशा में सरकार द्वारा कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, समाज कल्याण योजनाओं का सुदृढ़ीकरण और भविष्य की रणनीतियों का क्रियान्वयन इस क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगा। इन प्रयासों से न केवल नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि देश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

शिक्षा एवं अनुसंधान

उच्च शिक्षा पर ध्यान: भारतीय विश्वविद्यालयों, नए शैक्षणिक कार्यक्रमों और संस्थानों के भविष्य पर विशेष जोर भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में नए शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है। मल्टीडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देते हुए छात्रों को विविध कौशल विकसित करने के अवसर दिए जा रहे हैं। साथ ही, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे छात्रों को उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सके।

नए अनुसंधान केंद्र और पहल: बहु-विषयक अनुसंधान पर विशेष ध्यान सरकार और विश्वविद्यालय मिलकर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में, कई नए अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाजशास्त्र, पर्यावरण, और चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से बहु-विषयक अनुसंधान को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजा जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: वैश्विक अनुसंधान संगठनों के साथ साझेदारी भारतीय विश्वविद्यालय अब वैश्विक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ अपने सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। कई प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, संयुक्त शोध परियोजनाएं और फेलोशिप की शुरुआत की गई है। सरकार की 'स्टडी इन इंडिया' और 'ग्लोबल आउटरीच' योजनाएं भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का भविष्य: डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़ता रुझान भारत सरकार और निजी विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा के डिजिटलकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, और डिजिटल पुस्तकालयों का विकास हो रहा है, जिससे शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाया जा सके। साथ ही, विभिन्न विश्वविद्यालयों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी बल दिया जा रहा है, ताकि छात्रों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

अकादमिक क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना: नवाचार और उद्यमिता का समर्थन सरकार नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जहां छात्र और शोधकर्ता अपने स्टार्टअप विचारों को साकार कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार की नई पहलें और वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से उच्च शिक्षा को नए आयाम मिल रहे हैं। डिजिटल शिक्षा, अनुसंधान में नवाचार और अकादमिक स्टार्टअप की बढ़ती प्रवृत्ति भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY Madhya Pradesh, Khandwa AN AISECT GROUP UNIVERSITY | RNTU Rabindranath TAGORE UNIVERSITY MADHYA PRADESH, BHOPAL | AISECT UNIVERSITY JHARKHAND, HAZARIBAG AN AISECT GROUP UNIVERSITY | DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY Chhattisgarh, Bilaspur AN AISECT GROUP UNIVERSITY | SCOPE GLOBAL SKILLS UNIVERSITY | DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY Bihar, Vaishali AN AISECT GROUP UNIVERSITY

University Campus: Village Balkhadsura, Post - Chhaigaon Makhan, Khandwa, Madhya Pradesh - 450771 Phone: 07320-247700/01 | www.cvrukhandwa.ac.in | Connect with us: